

रजिस्ट्रेशन नं० ल-33/13-14/93.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 अप्रैल, 1993/13 चैत्र, 1915

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

प्रतिसूचना

शिमला-171002, 27 मार्च, 1993

संख्या गृह (ए०) ए० (9)-24/93.—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह रिपोर्ट की गई है कि 14-3-93 को श्री कांगड़ा के पुराने बस स्टैंड पर स्थित राजपूत सभा भवन में राजपूत सभा कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और लगभग

10.30 बजे प्रातः राजपूत सभा के सदस्यों ने पुराने बस स्टैंड की भूमि का वस्तुगत कब्जा लेने की दृष्टि से पुराने बस स्टैंड पर निर्माण सामग्री लाना आरम्भ कर दिया;

और यह भी रिपोर्ट की गई है कि कांगड़ा व्यापार मण्डल के लगभग 150 सदस्य पुराने बस स्टैंड पर पहुंच गए और उन्होंने राजपूत सभा के सदस्यों को भूमि का कब्जा लेने से रोका तथा व्यापार मण्डल के पक्ष में लगभग 2000 व्यक्ति इकट्ठे हो गए;

और अचानक ही दोनों ओर से पत्थर फेंकने शुरू हो गए और भीड़ ने राजपूत सभा के सदस्यों के 8 हल्के वाहन तथा एक मोटर साईकल जला दिया और 23 व्यक्ति घायल हो गए;

और 15-3-93 को प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए लगभग 500 व्यक्ति एकत्रित हुए और उन्होंने जय होटल से अचानक पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिए। 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गए और लाठी चार्ज करने का आदेश दिया गया तथा 91 व्यक्ति घायल हो गए;

और इस घटना ने लोक महत्व का रूप धारण कर लिया है;

और भारत के राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक महत्व के कुछ विनिर्दिष्ट मामलों की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त करना अत्याधिक समीचीन और लोकहित में होगा;

अतः भारत के राष्ट्रपति जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पी० सी० डोगरा, मण्डल आयुक्त कांगड़ा, धर्मशाला को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के विरुद्ध जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं:—

- (1) वे तथा और परिस्थितियां तथा जिनके कारण घटना हुई और उसके कारण;
- (2) जिला प्रशासन द्वारा भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए;
- (3) क्या जिला प्रशासन/पुलिस या सरकारी विभाग द्वारा कोई लापरवाही की गई थी;
- (4) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिशें;
- (5) कोई अन्य विषय जो जांच आयोग की राय में उक्त घटना से सुसंगत है।

इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति की यह राय है कि जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) के उपबन्ध आयोग को लागू किए जाने चाहिए, और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे। आयोग का मुख्यालय धर्मशाला में होगा और आयोग ऐसे स्थानों का दौरा भी कर सकता जो जांच को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है।

आदेश द्वारा,
एम० एम० मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

[Authorised text of notification No. Home (A)A(9) 24/93, dated 27-3-1993 under Article 345 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th March, 1993

No. Home (A)A (9)-24/93.—Whereas, it has been reported to the Government of Himachal Pradesh that on 14-3-1993 the Rajput Sabha executive meeting was held in Rajput Sabha Bhawan located at Old Bus Stand, Kangra and at about 10.30 A. M. Rajput Sabha Members started bringing construction material at the Old Bus Stand with a view to take physical possession of Old Land of Old Bus Stand;

And whereas, it has been reported that above 150 members of the Beopar Mandal Kangra reached Old Bus Stand and stopped Rajput Sabha members of taking possession of land and about 2000 persons gathered in favour of Beopar Mandal;

And whereas, suddenly stone throwing started from both sides and the crowd burnt 8 light vehicles and a motor-cycle belonging to members of the Rajput Sabha and 23 persons were injured;

And whereas, on 15-3-1993 about 500 people gathered raising slogans against administration and suddenly started throwing stones from Hotel Jai. 3 Senior Police Officer were injured and lathi charge was ordered and 91 persons were injured;

And whereas, this incident has assumed a great public importance;

And whereas, the President of India is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into certain specific matters of public importance;

Now, therefore the President of India in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiries Act, 1952, is pleased to appoint Shri P. C. Dogra, Divisional Commissioner, Kangra at Dharamshala as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to aforesaid incident, within one month from the date of issue of this notification:—

1. Facts and circumstances leading to the incident and the causes thereof;
2. What steps had been taken to control the mob/crowd by the district administration;
3. Was there any lapse on the part of District Administration/Police or Government Department;
4. To recommend steps to avoid recurrence of such incidents in future;
5. Any other matter which in the opinion of the Commission, is relevant to the incident.

Further, the President of India, is of the opinion that having regard to the nature of enquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (4) and 5 of section 5 of the Commission of Inquiry act should be made applicable

to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 5 of the aforesaid Act is pleased to direct that the provisions contained in sub-sections (2), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission. The headquarters of Commission of Inquiry would be at Dharamshala and may also visit such places as may be necessary in furtherance of the inquiry.

By order,

M. S. MUKERJEE,
Chief Secretary.